

Court No. - 48

Case :- WRIT - B No. - 3006 of 2023

Petitioner :- Rajrani Pal

Respondent :- State Of U.P. And 3 Others

Counsel for Petitioner :- Rajesh Kumar Bind, Shami Ullah

Counsel for Respondent :- C.S.C., Aakansha Singh, Deepraj Singh

Hon'ble Saurabh Shyam Shamsheery, J.

1. The conduct of petitioner, a lady, is not only against the well established etios of a family but also indicates how in order to justify mala fide intentions she has abandoned even name of her real husband after his death and has declared another person as her husband to achieve wrongful gain. There is an specific finding of Deputy Director of Consolidation in this regard, therefore, conduct of the petitioner was completely engrossed with fraud.

2 Learned counsel for petitioner has referred a death certificate, however, in this regard following finding of Deputy Director of Consolidation would be relevant to quote:

"उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस के आलोक में पत्रावली व अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया गया। ग्राम रेडी भुसौली के जो०चक०आ०प० चकदार सं० 44 कल्लू पुत्र जगन्नाथ द्वारा प्रस्तुत परिवार रजिस्टर की नकल जारी दिनांक 22.11.2022 व चक सं० पर अंकित चकबन्दी अधिकारी पारित आदेश आदेश मु० सं० 186 के अनुसार कल्लू पुत्र जगन्नाथ, काशीनाथ का पुरवा मजरा वियावल का निवासी है, जिसकी जाति केवट है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र जारी दिनांक 20.04.1004 में मृतक कल्लू पुत्र जगन्नाथ ग्राम रेडी भुसौली का निवासी तथा मृत्यु की तिथि 16.05.2004 अंकित है तथा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र जारी दिनांक 10.03.2023 पर राजरानी पाल पत्नी कल्लू पाल की जाति गडेरिया अंकित है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि ग्राम के चक सं० 44 का चकदार कल्लू पुत्र जगन्नाथ निवासी वियावल व वादिनी का मृतक पति कल्लू पुत्र जगन्नाथ निवासी रेडी भुसौली दोनों अलग-अलग व्यक्ति है। वादिनी द्वारा ग्राम में धारा 52 के प्रकाशन दिनांक 15.07.2004 व अपने पति की मृत्यु के 19 वर्ष पश्चात चकदार सं० 44 को अपना मृतक पति सिद्ध कर निवास स्थान बदलने का

कूटरचित प्रयास किया गया है। निगरानी निराधार है, आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।"

3. There is no material available with petitioner to refute above findings. The attempt of petitioner to get benefit on forged document not only remained unsuccessful but was completely failed due to impugned order.

4. A person who committed fraud is not entitled for any relief since it is well established principle of law that fraud vitiates every solemn act.

5. In view of above, no relief could be granted to petitioner. Writ petition is accordingly dismissed.

Order Date :- 13.10.2023

AK